[2013] 4 एस. सी. आर 797

उमेश सिंह

बनाम्

बिहार राज्य

आपराधिक अपील संख्या 43/2010 22 मार्च, 2013

[न्यायमूर्तिगण चंद्रमौली के. आर. प्रसाद और वी. गोपाल गौड़ा]

दंड संहिता, 1860 -धारा 302 सपठत धारा 34 हत्या-मृतक को रिवॉल्वर और राइफल से गोली मार दी गई-कई आरोपी-अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि-औचित्य-अभिनिर्धारित न्यायोचित-संबंधित चश्मदीद गवाह (पीडब्लू2) के बयान को सही ढंग से प्राथमिकी माना गया-पीडब्लू2 का साक्ष्य अन्य गवाहों द्वारा समर्थित (पीडब्लू3, पीडब्लू5 और पीडब्लू7)-अपीलार्थी का दावा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था, मान्य नहीं है-कानूनी आधार पर उसकी दोषसिद्धि अभिलेख पर साक्ष्य और उसी के उचित मूल्यांकन पर-शस्त्र अधिनियम -धारा 27।

साक्ष्य-कठोर मृत्यु-मृत्यु का समय-36 घंटे के बाद मृत शरीर से कठोर मृत्यु के पूरी तरह से गायब होने के बारे में डॉक्टर की राय-की शुद्धता-अभिनिर्धारित कियासही नहीं-चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा न्यायशास्त्र के नियम के विपरीत बयान दिया-तथ्यों पर, यह आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकता है।

साक्ष्य-चिकित्सा और नेत्र साक्ष्य के बीच विसंगति-प्रभाव-अभिनिर्धारित किया-मेडिकल और नेत्र साक्ष्य के बीच।

नेत्र साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जब मृतक अपने चचेरे भाई (पीडब्लू2) के साथ बस पकड़ने जा रहा था, तो आरोपी-अपीलार्थी और अन्य आरोपी अवधेश सिंह, सुधीर सिंह, जड्डू सिंह, नवल सिंह, बिंदा

सिंह जैसे लोगों ने घेर लिया। उसकी हत्या कर दी और उसके बाद रिवॉल्वर और राइफल से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। निचली अदालत (अपर सत्र न्यायाधीश) ने आरोपी व्यक्तियों को भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया और भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने जहाँ तक अवधेश सिंह, जड्डू सिंह और नवल सिंह का संबंध है की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया, जिन्हें भा.दं.वि. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया गया था, लेकिन अपीलार्थी के संबंध में दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

तत्काल अपील में, अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित किया- 1. 1.पी. डब्ल्यू. 2, मृतक का चचेरा भाई, घटना की तारीख पर उसके साथ था। उस समय अपीलार्थी ने अन्य अभियुक्तों के साथ उन्हें घेर लिया और यह कहा गया कि अपीलार्थी ने कानपट्टी पर रिवॉल्वर और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों बिंदा सिंह ने मृतक के पेट पर और सुधीर सिंह बाईं जांघ पर राइफल से गोली चला दिया। पीडब्लू 7 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उपरोक्त आरोपी व्यक्ति उस समय भाग गए थे जब अशोक सिंह, दामोदर सिंह, बलराम सिंह और श्याम सुंदर सिंह बाजार जा रहे थे जो घटना के गवाह थे। उसके साक्ष्य का समर्थन अन्य गवाह पी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य से होता है, जिसने कहा है कि उसने मोती सिंह और जड्डू सिंह को मृतक के दोनों हाथ पकड़ते देखा है और मोती सिंह ने उसे गोली चलाने का आदेश दिया है और उक्त गवाह ने अवधेश सिंह और नवल सिंह के द्वारा भी गोली चलाने के बारे में बताया है। जैसा कि पीडब्लू 2 ने कहा है।इसके अलावा, उन्होंने अपने सबूत का समर्थन किया है कि अवधेश सिंह ने शव को पाईन में धकेल दिया और कहा कि मोती सिंह और जड्डु सिंह ने सूचक को भी पकड़ लिया था। पीडब्लू5 ने यह भी दावा किया कि उसने जड्डू सिंह और मोती सिंह को मृतक का हाथ पकड़ते हुए देखा है और आगे उसने कहा है कि अपीलकर्ता उमेश सिंह ने मृतक के कनपटी पर गोली चलाई थी। इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है। कि बिंदा, सुधीर, अवधेश और नवल ने भी अपनी राइफलों से

मृतक पर गोलियां चलाई थीं।इसलिए, पीडब्लू-2 के साक्ष्य को पीडब्लू-3, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-7 द्वारा समर्थित किया गया है। जहाँ तक पीडब्लू 6 का संबंध है, उन्होंने एक सामान्य बयान में कहा गया कि उसने कई लोगों को मृतक को घेरते और मृतक को राइफल और रिवॉल्वर से मारते देखा है। इसलिए, निचली अदालत ने पीडब्लू-3 और पीडब्लू-5 द्वारा समर्थित चश्मदीद गवाह पीडब्लू-2 के साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पर निष्कर्ष दर्ज करने में सही था। इस अपीलार्थी और अन्य के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के आरोप पर तथ्य का उक्त निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से जांच की गई और उसी के साथ सहमति व्यक्त की गई और पीडब्लू 2 और पीडब्लू 9 के साक्ष्य को देखते हुए सूचना देने वाला जो चश्मदीद गवाह था और आई.ओ.पी. डब्ल्यू. 2 के बयान को एफ. आई. आर. के रूप में मानने वाले उनके साक्ष्य के बारे में उनका साक्ष्य पूरी तरह से कानूनी और वैध है। [कंडिका 14) [815-डी-एच; 816-ए-ई]

1.2 डॉक्टर-पीडब्लू 8 ने राय दी कि कठोरता मृत्यु 1 से 3 घंटे के भीतर शुरू होती है और 36 घंटे के बाद गायब हो जाती है। मृत्यु के 36 घंटे के बाद शव से अकड़न पूरी तरह से गायब होने के बारे में चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू8 की उक्त राय चिकित्सकीय रूप से सही नहीं है और यह इस विषय पर उनके ज्ञान की कमी हो सकती है और वे बचाव पक्ष के वकील द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए उदार थे। अपर सत्र न्यायाधीश ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि पी. डब्ल्यू. 8 चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा न्यायशास्त्र के नियम के विपरीत बयान दिया है, और इसलिए, अभियुक्त को बरी करने के लिए बचाव पक्ष के लिए यह आधार नहीं हो सकता है। अपर सत्र न्यायाधीश ने बी. एल. बंसल द्वारा लिखित मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस डाइजेस्ट का उल्लेख किया है, जिसमे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अकड़न मृत्यु के 12 से 24 घंटे तक बनी रहती है और फिर गुजर जाती है लेकिन इसका मतलब है कि कठोर मृत्यु जितनी तेजी से दिखाई देती है, उतना ही कम समय यह बनी रहती है। इसके अलावा, अपर सत्र न्यायाधीश ने ठीक ही कहा है बोलिन हुल्डर मामले को संदर्भित किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत के समान वातावरण में, अकड़न मृत्यु के एक से दो घंटे में शुरू

होता है और 18 से 24 घंटे के भीतर गायब होने लगता है। अपीलार्थी द्वारा यह दावा कि मृतक को पूर्ववर्ती समय पर मार दिया गया है और इस आरोप में आरोपी को गलत तरीके से फंसाया गया है, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में वैध और ठोस कारण बताते हुए इसकी सहमति दी गई है। राज्य के वकील ने उचित रूप से आग्रह किया है कि यदि चिकित्सा और नेत्र साक्ष्य विपरीत हैं तो नेत्र साक्ष्य प्रबल होना चाहिए। चिकित्सीय और नेत्र साक्ष्य के बीच, नेत्र साक्ष्य साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। [कंडिका 16] [819-बी-ई; 820-ए-डी]

अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 एस. सी. सी. 259:2010 (13) एस. सी. आर. 311 और बूलिन हुल्डर बनाम राज्य 1996 आपराधिक विधि/पत्रिका 513-पर निर्भर था।

ए. पी. बनाम राज्यपुनती रामुलु (1994) पूरक 1 एस. सी. सी. 590; ई. मुस्साउद्दीन अहमद बनाम असम राज्य (2009) 14 एस. सी. सी. 541; टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य/ए (2001) 6 एस. सी. सी. 181:2001 (3) एस. सी. आर. 942; देव पूजन ठाकुर बनाम बिहार राज्य (2005) पटना 1263; थंगावेलू बनाम तमिलनाडु राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 498; मोती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 9 एस. सी. सी. 444; कुंज मोहम्मद बनाम केरल राज्य एफ/ए (2004) 9 एससीसी 193; विरेन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 582:2008 (14) एससीआर 706; बासो प्रसाद बनाम बिहार राज्य (2006) 13 एससीसी 65:2006 (9) पूरक।एस. सी. आर. 431; विनय कुमार बनाम बिहार राज्य (1997) 1 एस. सी. सी. 283:1996 (8) पूरक एस. सी. आर. 225 और दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य (2008) 8 जी सेकण्ड 270:2008 (11) एस. सी. आर. 843-उद्धृत।

बी. एल. बंसल अधिवक्ता द्वारा मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस डाइजेस्ट, (पृष्ठ 422 पर 1996 संस्करण)-संदर्भित।

2. दोषसिद्धि और अधिरोपित सजा का आदेश अपीलार्थी के खिलाफ रिकॉर्ड पर कानूनी साक्ष्य के आधार पर और उसी के उचित मूल्यांकन पर है। वह कानून में गलत नहीं है क्योंकि निष्कर्ष वैध और ठोस कारणों से समर्थित है। [कंडिका 17] [820-एफ-जी]

मामला कानून संदर्भ

(1994) पूरक 1 एस. सी. सी. 590	ने	कंडिका 4
(2009) 14 एस. सी. सी. 541	उद्धृत	कंडिका 5
2001 (3) एस. सी. आर. 942	उद्धृत	कंडिका 6
(2005) पटना 1263	ने	कंडिका 6
(2002) 6 एस. सी. सी. 498	उद्धृत	कंडिका 8
(2003) 9 एस. सी. सी. 444	उद्धृत	कंडिका 8
(2004) 9 एस. सी. सी. 193	उद्धृत	पैरा 8
2008 (14) एस. सी. सी. 706	उद्धृत	कंडिका 8
2006 (9) पूरक एस. सी. आर. 431	ने	कंडिका 8
1996 (8) पूरक एस. सी. आर. 225	ने	पैरा 10
2008 (11) एस. सी. आर. 843	का हवाला दिया	पैरा 11
2010 (13) एस. सी. आर. 311	ने	पैरा 15
1996 आपराधिक विधि पत्रिका 513	पर भरोसा किया	पैरा 16

1998 की आपराधिक अपील संख्या 318 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.05.2003 के कंडिका 16 पर भरोसा किया।

अपीलार्थी के लिए अमरेंद्र शरण, समीर अली खान, ध्रुव पाल, सोमेश चंद्र झा, अपराजित मुखर्जी।

प्रतिवादी की ओर से चंदन कुमार, गोपाल सिंह।

न्यायालय का निर्णय दिया गया।

निर्णय

वी. वी. गोपाल गौड़ा, न्यायमूर्ति

यह अपील अपीलार्थी द्वारा, विभिन्न तथ्यों और कानूनी प्रतिवादों का आग्रह करते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा ३४ और शस्त्र अधिनियम की धारा २७ के साथ पठित धारा ३०२ के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि करते हुए, १९९८ के आपराधिक दंड संहिता की संख्या २४१, २४७, २७१ और ३१८ में २२ और मई, २००३, दिनांकित आम निर्णय से व्यथित होकर दायर की गई हैहै। अपीलकर्ता इसमें उच्च न्यायालय के समक्ष 1998 की दंड प्रक्रिया संहिता संख्या 318 में अपीलार्थी था।उक्त मामले में पारित आक्षेपित निर्णय इस अपील में चुनौती के अधीन हैहै।

2. अभियोजन मामले के संबंध में संक्षिप्त तथ्य यहां यह पता लगाने के लिए कि क्या इस न्यायालय को अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि में दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, पक्षकारों की ओर से आग्रह किया गया है।

3. मृतक शैलेन्द्र कुमार की हत्या 16.07.1996 को अपराह्न लगभग 3.30 बजे अपीलार्थी उमेश सिंह और अन्य व्यक्तियों, नामतः अवधेश सिंह, सुधीर सिंह, जड्डू सिंह, नवल सिंह, बिंदा सिंह उर्फ बिंदेश्वरी सिंह ने अन्य अभियुक्तों के साथ साझा इरादे को आगे बढ़ाने के आपराधिक इरादे से रिवॉल्वर और राइफल से गोली मारकर की थी और उनके पास अवैध उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने के इरादे से आग्नेयास्त्रों को

अपने कब्जे में रखा था। शैलेंद्र कुमार की हत्या के मामले में आरोपी नं.5 और 6 तथा एक अन्य अभियुक्त मोती सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक अपने चचेरे भाई अरविंद कुमार-अभियोजन साक्षी 2 के साथ 16.7.96 को लगभग 3.30 बजे कोथार के लिए एक बस पकड़ने के लिए तुंगी जा रहा था। मृतक आरोपी मोती सिंह ने कथित तौर पर अपने अन्य सहयोगियों को मृतक शैलेंद्र कुमार को गोली मारने के लिए प्रेरित किया था, जिस पर अपीलार्थी ने एक देशी रिवॉल्वर निकाली और मृतक के मंदिर में अपनी गोलियां चलाईं और आरोपी नं.2 जिसके हाथ में राइफल थी, मृतक के पेट में गोली चलाई गई। आरोपी नं.4 ने एक गोली भी चलाई जिससे मृतक के पैर में चोट लगी जबकि आरोपी नं.3 ने अपनी राइफल से भी गोली चलाई। आरोपी नं.5 के पास एक राइफल भी थी और उसने मृत शरीर पईन में फेंक दिया। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि घटना की घटना के दौरान मुखबिर पी डब्लू २ अरविंद कुमार को मृतक अभियुक्त मोती सिंह और जड्डू सिंह द्वारा अत्यधिक शक्ति दी गई थी और लक्ष्य को पूरा करने के बाद वे चले गए.इसके अलावा, जिन गवाहों के नाम फरदबियां में पाए गए, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने घटना को देखा है। एएसआई आर. एस. सिंह ने उसी दिन लगभग शाम 7 बजे तुंगी हाई स्कूल हॉस्टल, लतावर पायीन में फरदबियान रिकॉर्ड किया और घटनास्थल से बरामद खाली कारतूस सहित कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं की जब्त सूची भी तैयार की गई। औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच पूरी होने पर, पुलिस ने विद्वत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संज्ञान लिया गयाहै। उनके द्वारा यह मामला सेशन कोर्ट को सौंपा गया था। विद्वत सत्र न्यायाधीश ने अपनी बारी पर मामले को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, नवादा की फाइल में स्थानांतरित कर दिया और आईपीसी की धारा 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित अपराध के लिए आरोप तय किए गए।मामला सुनवाई के लिए चला गया और अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 से पीडब्लू-9 तक गवाहों की जांच की और बचाव पक्ष के समर्थन में दो गवाहों से पूछताछ की गई.विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य और अभिलेख के मूल्यांकन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दोषसिद्धि और दंड

अधिरोपित करते हुए दिनांक 04.04.1998 का निर्णय पारित किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत आजीवन कारावास का दंड दिया। दोषसिद्धि और पारित दंडादेश अपर सत्र न्यायाधीश को अभियुक्त द्वारा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष ऊपर निर्दिष्ट अपीलों में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्तों/अपीलार्थियों को सुनने के बाद वर्तमान अपीलार्थी के संबंध में दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि करते हुए सामान्य निर्णय पारित किया और जहां तक अवधेश सिंह, जड्डू सिंह और नवल सिंह का संबंध है, जिन्हें आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत आरोपों का दोषी नहीं पाया गया था, अर्थात् अपील संख्या में दोषसिद्धि और दंडादेश को रद्द कर दिया। 241/98 और 247/98।हालांकि, जहां तक वर्तमान अपीलार्थी और अन्य का संबंध है, विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की गई थी.अपीलों के लंबित रहने के दौरान अभियुक्त मोती सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी अपील समाप्त हो गई।

4. अपीलकर्ता ने दूसरों के साथ उसके खिलाफ दोषसिद्धि और दिए गए दंड की पुष्टि करने में उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में दर्ज निष्कर्षों की सत्यता पर सवाल उठाया है। श्री अमरेंद्र शरण अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियों पर ध्यान देने में विफल रहा है, यह उसी पर अविश्वास कर सकता था, लेकिन उसने इस अपीलार्थी पर दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है। इसके अलावा, अपने स्वयं के निष्कर्षों के अनुसार, घटना के लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं था क्योंकि पीडब्लू घटना के 15-20 मिनट बाद घटना के स्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर मौजूद मुखबिर ने साक्ष्य और अपीलकर्ता की भूमिका के बारे में एफआईआर में अलग-अलग बयान दिया है। मृतक के चचेरे भाई पी डब्लू २ अरविंद कुमार के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच अधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई थी। पीडब्लू 2 घटना के समय मौजूद था और उसके बयान के आधार पर, आरोपी व्यक्तियों को उसके बयान को एफआईआर के रूप में लेने में गलत तरीके से फंसाया गया है, जो कि विलंबित

एफआईआर है। जो कानून में स्वीकार्य नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा भी प्रभावित है। आंध्र प्रदेश राज्य v.पुनति रामुलु सुसंगत पैराग्राफ इस प्रकार हैंः

> "3 हमारी राय में, प्रत्यर्थियों की रिहाई दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित कारण साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित हैं। निष्कर्ष न केवल सबूतों के उचित मूल्यांकन द्वारा समर्थित हैं, बल्कि तर्कसंगत और ठोस भी हैं।दागी जांच के कारण, कृष्णा राव की हत्या को सजा नहीं मिलती है। लेकिन हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि चूंकि बचाव पक्ष पुलिस जांच की ईमानदारी को सफलतापूर्वक चुनौती देने में सक्षम रहा है, इसलिए इसने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में अन्य साक्ष्यों की विश्वसनीयता को भी भौतिक रूप से कम कर दिया है।
>
> 5. एक बार जब हम पाते हैं कि जांच अधिकारी जानबूझकर प्रकृति के संज्ञेय अपराध की जानकारी प्राप्त करने पर पहली सूचना रिपोर्ट रिकॉर्ड करने में विफल रहा है, जैसा कि इस मामले में है, और उचित विचार-विमर्श, परामर्श और चर्चा के बाद घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पहली सूचना रिपोर्ट तैयार की थी, तो निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि जांच दागदार है और इसलिए ऐसी दागदार जांच पर भरोसा करना असुरक्षित होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि पुलिस अधिकारी सबूत बनाना और गलत सुराग बनाना कहां बंद कर देता।हालांकि हम इस बात से सहमत हैं कि केवल गवाहों पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 का संबंध है, मृतक के बच्चे या पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 के बच्चे जो भी इस मामले से संबंधित हैं। यह कि साक्ष्य के संबंध या पक्षपातपूर्ण स्वरूप ने न्यायालय को केवल साक्ष्य की और अधिक सावधानी से जांच करने के लिए सतर्क कर दिया है, हम पाते हैं कि इस मामले में जब जांच की सद्भावना पर सफलतापूर्वक हमला किया गया है, तो इन गवाहों की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा

> या तो इस मामले में एक मजबूत संपुष्टि वाले साक्ष्य के अभाव में, जो इस मामले में नहीं पाया गया है।"

5. विद्वत वरिष्ठ वकील द्वारा आगे प्रतिवाद किया गया कि पी डब्लू 4 द्वारा पुलिस को दी गई पहले की जानकारी को दबा दिया गया था और उस समय तक पी डब्लू 9-आई ओ घटना स्थल पर पहुंच गया था, अन्य पुलिस अधिकारी और जिले के एस पी बहुत अधिक उपस्थित थे। आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए मामले में उनकी जांच नहीं की गई थी। उपर्युक्त व्यक्तियों की अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में गैर-परीक्षा, जो अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण गवाह हैं, मामले के लिए घातक है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मुसौद्दीन अहमद बनाम असम राज्य वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। उपरोक्त मामले का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैः

> "11. पक्षकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने कब्जे के सर्वोत्तम साक्ष्य का नेतृत्व करे जो विवाद में मुद्दे पर प्रकाश डाल सके और यदि ऐसा तात्विक साक्ष्य रोक लिया जाता है, तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 चित्रण (छ) के अधीन प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है, इस बात के होते हुए भी कि सबूत की जिम्मेदारी ऐसे पक्षकार पर नहीं है और उक्त साक्ष्य प्रस्तुत प्रस्तुत के लिए नहीं कहा गया था (देखिए गोपाल कृष्णाजी केतकर बनाम मोहम्मद अशरफ, ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 581) हाजी लतीफ)"

6. अपीलार्थी के विद्वत वरिष्ठ वकील ने आगे प्रतिवाद किया कि पी डब्लू 4 द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी को एफ आई आर के रूप में अभिलिखित नहीं करना, लेकिन पी डब्लू 2 जानकारी को मामले में एफ आई आर के रूप में मानना, यद्यपि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा प्रभावित है, अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह पैदा करता है और इसलिए निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के

फैसले पर भरोसा किया है। टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य में रिपोर्ट की गई। प्रासंगिक पैराग्राफ यहां उद्धृत किए गए हैंः

> “18. सीआरपीसी की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत दी गई जानकारी को आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के रूप में जाना जाता है, हालांकि संहिता में इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और जैसा कि इसके उपनाम से पता चलता है कि यह किसी संज्ञेय अपराध की सबसे पहले और पहली प्राथमिकी थाना के प्रभारी द्वारा दर्ज की गई। यह आपराधिक कानून को गति देता है और जांच की शुरुआत को चिह्नित करता है जो सीआरपीसी की धारा 169 या 170 के तहत राय बनाने और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट को अग्रेषित करने के साथ समाप्त होता है।एक फोन कॉल या एक क्रिप्टिक टेलीग्राम द्वारा अस्पष्ट जानकारी के अलावा, इस उद्देश्य के लिए एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा पहली बार स्टेशन हाउस डायरी में दर्ज की गई जानकारी पहली सूचना है-सीआरपीसी की धारा 154 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर. प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से संज्ञेय अपराध की जांच शुरू होने के बाद मौखिक या लिखित रूप से या पुलिस अधिकारी द्वारा स्टेशन हाउस डायरी में दर्ज किए गए अन्य संज्ञेय अपराध या जांच के दौरान उसके संज्ञान में आने वाले ऐसे अन्य संज्ञेय अपराध, सीआरपीसी की धारा 162 के तहत आने वाले बयान होंगे। आइए हम एक अलग स्थिति पर विचार करें जिसमें एच ने डब्ल्यू, उसकी पत्नी को मार डाला है, पुलिस को सूचित करता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या की गई है या यह जानते हुए कि डब्ल्यू उसकी मां या बहन द्वारा मारा गया है, एच जिम्मेदारी लेता है और जांच के दौरान सच्चाई का पता चलता है-यह एच के खिलाफ ताजा एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता

नहीं है-वास्तविक अपराधी-जिसे सीआरपीसी की धारा 173 (2) या 173 (8) के तहत रिपोर्ट में आरोपित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।जांच अधिकारी के लिए यह निश्चित रूप से अनुज्ञेय है कि वह संबंधित मजिस्ट्रेट को पहले ही यह रिपोर्ट भेज दे कि संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ जांच का निर्देश दिया जा रहा है।

19. दंड प्रक्रिया संहिता की स्कीम यह है कि किसी संज्ञेय अपराध के होने की जानकारी मिलने पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रवेश के आधार पर, किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 या 157 में यथा उपबंधित जांच आरंभ करनी होगी। जांच पूरी होने पर और एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर उसे सीआरपीसी की धारा 169 या 170 के तहत राय बनानी होगी और सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी।

20. उपर्युक्त चर्चा से यह पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154, 155, 156, 157, 162, 169, 170 और 173 के उपबंधों की स्कीम के अधीन किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में केवल आरंभिक या प्रथम सूचना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की अपेक्षाओं को पूरा करती है।किसी संज्ञेय अपराध या किसी संज्ञेय अपराध या अपराध को बढ़ावा देने वाली किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होने और स्टेशन हाउस डायरी में एफआईआर दर्ज करने पर, किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को न केवल एफआईआर में दर्ज संज्ञेय अपराध की जांच करनी होती है, बल्कि उसी लेनदेन या उसी घटना के दौरान किए गए अन्य संबंधित अपराधों की भी जांच करनी होती है और सीआरपीसी की धारा 173 में दिए गए प्रावधान के अनुसार एक या अधिक रिपोर्ट दर्ज करनी होती है।"

इसके अतिरिक्त, पटना उच्च न्यायालय ने देव पूजन ठाकुर बनाम बिहार राज्य के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

> "18. रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य और बहस के दौरान बचाव पक्ष द्वारा लाई गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष ने पहली जानकारी को अभिनिर्धारित किया और इसे अदालत के समक्ष कारणों से प्रस्तुत नहीं किया।"इसने स्वतंत्रता गवाह की जांच नहीं की, हालांकि इनमें से कुछ नामों का उल्लेख अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में किया गया है और उनमें से कुछ तब भी चार्जशीट गवाह थे, केवल परिवार के सदस्यों और इच्छुक गवाहों से जो प्रतिकूल हैं, की जांच की गई है।जिस फरदबियान के आधार पर औपचारिक एफआईआर तैयार की गई थी, उस पर सीआरपीसी की धारा १६२ द्वारा प्रहार किया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ-साथ पीडब्लू ११ के साक्ष्य ने मामले के बचाव पक्ष के संस्करण की पुष्टि की है कि मृतक की हत्या एक सुनसान जगह पर की गई थी जब वह प्रकृति की पुकार में भाग लेने के बाद आ रहा था। मामले की परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष का संस्करण विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहे हैं। निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला और दोषसिद्धि का आदेश बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं है।"

7. यह आगे विद्वत वरिष्ठ वकील द्वारा प्रतिवाद किया गया कि अन्य पीडब्लू जिनकी मामले में अत्यधिक रुचि थी, उनकी जांच की गई थी। स्वतंत्रता गवाह उपलब्ध थे लेकिन अभियोजन पक्ष ने मामले में उनकी जांच नहीं की। इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला स्वतंत्रता गवाहों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए जांच न करने के लिए घातक है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ धारा ३०२ के साथ पठित धारा ३४ के तहत आरोप पर समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया गया है। अपीलार्थी

कानूनी रुप से गलत है। उच्च न्यायालय पी डब्लू २ के साक्ष्य को ध्यान में रखने में विफल रहा है, जो, अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक मुखबिर है। अपने साक्ष्य में उसने कहा है कि मृतक का शव उसके बाद बरामद किया गया था और वह अन्य गवाहों के साथ घटना के स्थान पर रहा और उनमें से कोई भी पुलिस को सूचित करने के लिए पुलिस थाने नहीं गया। पी डब्लू ३ दामोदर सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचित करने नहीं गया, लेकिन पी डब्लू ४ अशोक कुमार ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसका बयान एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था, जहां उसने कहा था कि उसने पुलिस को जानकारी भेजी थी। पी डब्लू ९-आई. ओ. ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि अशोक सिंह-पी डब्लू ४ की सूचना पर वह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी और कई अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर गए थे। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय कॉलम सं. 1 फरदबियान के अधीन एफ. आई. आर. में वर्णित मामले के सुसंगत पहलू को ध्यान में रखने में विफल रहा है और एफ. आई. आर. 16.07.1996 को रात्रि 10.00 बजे दर्ज की गई थी। घटना स्थल और पुलिस स्टेशन की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है।पी डब्लू 9 के अनुसार, दिनांक 16.07.1996 को अपराह्न 10 बजे के बाद आई ओ, वह बदल दिया गया था, इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करता है कि पी डब्लू 4 अशोक कुमार और पी डब्लू 9 के साक्ष्य के आधार पर और पी डब्लू 2 के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए इस न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट विनिश्चयों में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में विधि में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा प्रभावित है पुलिस द्वारा एफ आई आर के पंजीकरण के संबंध में पूर्वोक्त तथ्यों और कानूनी साक्ष्य को देखते हुए विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया जाना चाहिए था। यह न्यायिक निष्कर्ष है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा प्रभावित पीडब्लू 2 के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करना इस मामले के गवाहों की प्रेरणा पर आरोपी के खिलाफ मामले में हेरफेर का परिणाम है और पीडब्लू 4 द्वारा पुलिस स्टेशन को दी गई पहली जानकारी को इस कारण दर्ज नहीं करना कि यह सुनी गई थी।मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू का अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा लोप किया गया है।इसलिए, अपीलार्थी और अन्य के खिलाफ लगाए गए

आरोप पर आक्षेपित निर्णय में दर्ज निष्कर्ष कानून में गलत है और इसे रद्द किया जा सकता है.इसके अलावा, निचली अदालतें इस तथ्य को समझने में विफल रही हैं कि मृतक शैलेंद्र कुमार की हत्या करने के लिए अपीलार्थी का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस मामले में गवाहों द्वारा आरोपी को गलत तरीके से फंसाने का इरादा था.विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने पी डब्लू ४ अशोक कुमार के साक्ष्य पर भरोसा किया जिसमें उसने कहा है कि अवध सिंह आरोपी बिंदा सिंह का भाई है, जिसने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था और आरोपी उमेश सिंह और नवल के पिता भुनेश्वर सिंह गवाह थे और पीडब्लू 5 बलराम सिंह जो मृतक शैलेंद्र कुमार के पूर्ण भाई हैं, ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि आरोपी और स्वयं के साथ और मृतक सहित उसके दो भाइयों के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी।

8. इसके अतिरिक्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि उच्च न्यायालय चिकित्सा साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहा है, जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 16.07.1996 को अपराह्न 3.30 बजे हुई, जब मृतक अपने ग्राम के घर से अपनी ड्यूटी में शामिल होने जा रहा था। रिकॉर्ड पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर, कॉलम नंबर 21 से 23, पीडब्लू8 में, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि न केवल मृतक का पेट, बल्कि दोनों मूत्राशय खाली थे और मृत्यु के बाद से 30 से 36 घंटे बीत गए। इसके कारण घटना 16.07.1996 के शुरुआती घंटों में हुई होगी क्योंकि मृतक का खाली पेट होना चाहिए। इसके अलावा, पीडब्लू ८ के साक्ष्य में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का विवरण भी गवाहों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार नहीं है। पी डब्लू ८ डॉक्टर ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम परीक्षण के समय से ३० घंटे से पहले हुई होगी.इसका अर्थ है कि घटना की कोई घटना 16.07.1996 को अपराह्न 3.30 बजे नहीं हुई, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित किया गया था और मृतक घटना के अभिकथित समय से पहले मर गया था। इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप नहीं है, बल्कि यह पूरे अभियोजन पक्ष के मामले को झूठा साबित करने वाले बचाव पक्ष का समर्थन करता है। इस संबंध में उसने इस

न्यायालय द्वारा रखी गई विधि की प्रस्तावना पर इस प्रभाव के लिए दृढ़ता से भरोसा किया है कि एक बार मृत्यु का समय, जैसा कि अभियोजन द्वारा दावा किया गया है, बिल्कुल अलग है। चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है और संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना चाहिए।उन्होंने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है, थंगावेलु बनाम तमिलनाडु राज्य, मोती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कुंजू मोहम्मद बनाम केरल राज्य, वीरेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और बासो प्रसाद बनाम बिहार राज्य।

9. इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करता है कि इस अपीलार्थी के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज आरोप पर तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष गलत है और कानून में त्रुटि है, जिसे रद्द किया जा सकता है और उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जा सकता है और उसे इस अपील को मंजूर करके स्वतंत्र किया जा सकता है।

10. दूसरी ओर, श्री चंदन कुमार, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता ने न्यायालय में अभिलिखित निष्कर्ष और कारणों को न्यायोचित ठहराने की मांग की। आक्षेपित निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रतिवाद करते हुए कि उच्च न्यायालय ने अपनी अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोपों पर विद्वत सेशन न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों और कारणों की सत्यता की जांच की है और उसके उचित मूल्यांकन पर, उसने अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की है जो अभिलेख पर साक्ष्य के उचित पुनर्मूल्यांकन पर आधारित है। इसका समर्थन वैध और ठोस कारणों से किया जाता है। विद्वत वकील ने पीडब्लू २ द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्राथमिकी के पंजीकरण को उचित ठहराने की मांग की, जो इस निर्णय के अनुरूप है। विनय कुमार बनाम बिहार राज्य में न्यायालय प्रासंगिक इस प्रकार है:

> "9. लेकिन हमें इस मामले में प्राथमिकी तैयार करने के उद्देश्य से एक्सटेंशन 10/3 को प्रथम सूचना बयान के रूप में नहीं लेने में पुलिस की ओर से कोई त्रुटियां नहीं मिली है। यह स्पष्ट रूप से एक गोपनीय जानकारी है और इससे किसी संज्ञेय अपराध के होने को समझने के लिए शायद ही पर्याप्त है। संहिता की धारा 154 के तहत सूचना को निश्चित रूप से संज्ञेय अपराध से संबंधित होना चाहिए और इसे लिखित रूप में (यदि मौखिक रूप से दिया जाए) कम किया जाना चाहिए और इसके निर्माता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अगली आवश्यकता यह है कि उसका सार पुलिस थाने में रखी गई पुस्तक में ऐसे प्ररूप में दर्ज किया जाए जैसा कि राज्य सरकार ने विहित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) तैयार की जानी है और इसे उस मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाएगा, जिसे ऐसी रिपोर्ट पर इस तरह के अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है। किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में किसी प्रामाणिक जानकारी का खुलासा नहीं करने वाले किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी अस्पष्ट जानकारी पर प्राथमिकी तैयार करने के लिए बाध्य नहीं है।प्रभारी अधिकारी घटना, यदि उपलब्ध हो, के बारे में विवरण वाली अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए स्वतंत्र है, ताकि वह इस बात पर विचार कर सके कि क्या कोई संज्ञेय अपराध जांच के लिए किया गया है।"

11. इसके अतिरिक्त, इसकी शुद्धता को आई. ओ. के साक्ष्य पर भरोसा करके न्यायोचित ठहराने की कोशिश की जाती है।राज्य के वकील ने दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं:

> "11. यह ध्यान देने योग्य है कि पी डब्लू ७ और १३ घायल गवाह थे और पी डब्लू १० एक अन्य चश्मदीद गवाह और मुखबिर था।

विधि काफी अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही सह-अभियुक्त के संबंध में इस आधार पर दोषमुक्ति अभिलिखित की जाती है कि इसमें अतिशयोक्ति और अलंकरण थे, फिर भी दोषसिद्धि को अभिलिखित किया जा सकता है यदि साक्ष्य दूसरे अभियुक्त के संबंध में ठोस, विश्वसनीय और सत्य पाया जाता है। केवल यह तथ्य कि गवाह मृतक से संबंधित थे, उनके साक्ष्य को खारिज करने का एक आधार नहीं हो सकता है।

12. कानून में, घायल साक्षी की गवाही को महत्व दिया जाता है। जब प्रत्यक्षदर्शियों को अभियुक्त के प्रति हितबद्ध और प्रतिकूल रूप से निपटाया गया कहा जाता है, तो यह नोट किया जाना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाएंगे और निर्दोष व्यक्तियों को फंसाएंगे। साक्ष्य की सच्चाई या अन्यथा को व्यावहारिक रूप से तौला जाना चाहिए। अदालत को संबंधित गवाहों और उन गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी जो अभियुक्त के प्रति प्रतिकूल रूप से निपटाए गए हैं। लेकिन यदि उनके साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और जांच के बाद, गवाहों द्वारा दिया गया बयान स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय प्रतीत होता है, तो इसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है। ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।"

12. विद्वत वकील आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के विद्वत वकील द्वारा प्रतिवाद किए गए अनुसार घटना के स्थान के संबंध में विवाद तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। घटना के स्थान के बारे में उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए बहुत निश्चित है क्योंकि यह टुंगी में कहा जाता है। पी डब्लू ४ अशोक कुमार सिंह ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह एक चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन सुनी-सुनाई के आधार पर उसने पुलिस को सूचित किया है। अन्वेष्क अधिकारी ने अपने साक्ष्य में आगे कहा है कि पी डब्लू ४ एक सुनी सुनाई गवाह है और इसलिए उसकी

जानकारी को एफ आई आर के रूप में नहीं माना जा सकता था। इसलिए उसने इस न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, विशेष रूप से, विधिक साक्ष्य और अभिलेख के उचित मूल्यांकन पर उच्च न्यायालय द्वारा आरोप पर समवर्ती निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत आरोप के लिए दोषसिद्धि और दंड की पुष्टि करते हुए।

13. पक्षकारों की ओर से आग्रह किए गए प्रतिद्वंद्वी कानूनी दावों की पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने इस निर्णय में ऊपर दिए गए बिंदु का जवाब देने और निम्नलिखित कारणों से अपीलकर्ता के खिलाफ उसी का जवाब देने के लिए उचित रूप से विचार किया है।

14. पीडब्लू-2 अरविंद कुमार, जो मृतक का चचेरा भाई है, घटना की तारीख पर उसके साथ था। उस समय अपीलार्थी ने, अन्य अभियुक्तों के साथ, उन्हें घेर लिया और यह कहा गया है कि अपीलार्थी ने रिवॉल्वर और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों बिंदा सिंह के साथ कानपट्टी पर गोली चलाई। मृतक के पेट में राइफल और बायीं जांघ में राइफल के साथ सुधीर सिंह। पी डब्लू ७ ने अपने साक्ष्य में कहा है कि पूर्वोक्त अभियुक्त व्यक्ति उस समय भाग गए थे अशोक सिंह, दामोदर सिंह, बलराम सिंह और श्याम सुंदर सिंह बाजार जा रहे थे जिन्होंने घटना को देखा है। उसके साक्ष्य को अन्य गवाह पी डब्लू ३ के साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया है, जिसने कहा है कि उसने मोती सिंह और जड्डू सिंह को मृतक का दोनों हाथ पकड़ते हुए देखा है और मोती सिंह ने उसे गोली मारने का आदेश दिया है और उक्त गवाह ने अवधेश सिंह और नवल सिंह द्वारा गोलीबारी किए जाने के बारे में भी बताया जैसा कि पी डब्लू २ द्वारा कहा गया है। इसके अलावा, उसने अपने साक्ष्य का समर्थन किया है कि अवधेश सिंह ने मृत शरीर को पायेन में धकेल दिया था और यह भी कहा कि मोती सिंह और जड्डू सिंह ने मुखबिर को भी पकड़ लिया था। पी डब्लू ५ ने यह भी दावा किया कि उसने जड्डू सिंह और मोती सिंह को मृतक का हाथ पकड़ते हुए देखा है और आगे उसने कहा है कि इसमें अपीलार्थी उमेश सिंह ने मृतक के मंदिर क्षेत्र पर गोली चलाई थी। इसके अलावा, उसने स्पष्ट बयान दिया है कि बिंदा, सुधीर, अवधेश और नवल ने भी अपनी राइफलों से मृतकों पर गोली चलाई थी।

इसलिए, पीडब्ल्यू 2 के साक्ष्य को पीडब्ल्यू3, पीडब्ल्यू5 और पीडब्ल्यू7 द्वारा समर्थित किया गया है. जहां तक पी डब्ल्यू 6 का संबंध है, उसने एक सामान्य बयान दिया है कि उसने मृतक के आस-पास के कई व्यक्तियों को देखा है और राइफल और रिवॉल्वर से मृतक की हत्या की है। इसलिए, निचली अदालत पीडब्लू 3 और पीडब्लू 5 द्वारा समर्थित चश्मदीद गवाह पीडब्लू 2 के साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पर निष्कर्ष दर्ज करने में सही थी। इस अपीलार्थी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा ३४ के साथ पठित धारा ३०२ के आरोप पर तथ्य का कथित निष्कर्ष की उच्च न्यायालय द्वारा गंभीरता से जांच की गई थी और उसके साथ सहमति व्यक्त की गई थी और पी डब्लू २ और पी डब्लू ९ के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो चश्मदीद गवाह था और पी डब्लू २ के बयान को एफ आई आर के रूप में मानने के संबंध में उसके साक्ष्य के बारे में आई ओ का साक्ष्य पूरी तरह से कानूनी और वैध है। इसलिए, इसके उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा किया गया। विद्वत वरिष्ठ वकील द्वारा अपनी प्रस्तुति के दौरान ऊपर संदर्भित न्यायालय कानून में मान्य नहीं है क्योंकि वे गलत हैं।

15. जहां तक डॉक्टर-पी डब्लू 8 के चिकित्सीय साक्ष्य को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पढ़ा गया है, जिस पर अपीलार्थी के विद्वत वरिष्ठ वकील द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया जाता है कि मृत्यु डॉक्टर द्वारा दी गई राय के अनुसार 30 से 36 घंटे से पहले हुई होगी, जिसका अर्थ है कि यह 16.07.1996 के शुरुआती घंटों से संबंधित है, लेकिन अपराह्न 3.30 बजे नहीं जैसा कि प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है। एक बार मृत्यु का समय अभियोजन द्वारा दावा किए गए मामले से काफी अलग हो जाता है, तो उसके मामले को कानून में दूषित कर दिया जाता है। उपरोक्त तर्क के समर्थन में, पूर्वोक्त मामलों पर इस न्यायालय के निर्णयों पर मजबूत निर्भरता सभी गलत हैं क्योंकि वे अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्यके अनुसार यह निर्धारण गलत है, इससे संबंधित पैराग्राफ यहाँ उद्धृत किया गया है-

> “33. हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ वाले मामले में यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः (एससीसी पृ. 101, पैरा 15)

> "15. चिकित्सा साक्षी द्वारा दी गई राय को इस विषय पर अंतिम शब्द होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी राय-अदालत द्वारा परीक्षण किया जाए।यदि राय तर्क या वस्तुनिष्ठता से वंचित है, तो न्यायालय उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है।आखिर किसी तथ्य की स्थिति के बारे में किसी व्यक्ति के मन में जो राय बनती है, वही राय होती है। यदि एक चिकित्सक एक राय बनाता है और दूसरा चिकित्सक एक ही तथ्य पर अलग राय बनाता है तो न्यायाधीश को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना जो अधिक वस्तुनिष्ठ या संभावित हो। इसी प्रकार यदि एक चिकित्सक द्वारा दी गई राय संभाव्यता के अनुरूप नहीं है तो न्यायालय की उस राय को मानने की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि यह डॉक्टर द्वारा कही गई है।निश्चित रूप से, उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए विचारों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए जो किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ हैं।"

34. भगीरथ मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र साक्ष्य से भिन्न है, यह नोट किया जाना चाहिए कि प्रत्यक्षदर्शियों के खाते को बाहर करने के लिए चिकित्सा गवाहों के काल्पनिक उत्तरों को अनुचित प्राथमिकता देना गलत होगा, जिसका स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना था और चिकित्सा साक्ष्य को 'स्थिर' के रूप में रखते हुए 'चर' के रूप में नहीं माना जाना था।

35. जहां प्रत्यक्षदर्शियों का विवरण विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इंगित करने वाली चिकित्सीय राय को निश्चायक नहीं माना जा सकता है।प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण के लिए इसकी विश्वसनीयता के लिए सावधानीपूर्वक

स्वतंत्रता रुप में और मूल्यांकन की आवश्यकता है, जिसे ऐसी विश्वसनीयता की कसौटी के लिए एकमात्र कसौटी के रूप में चिकित्सा साक्ष्य सहित किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर प्रतिकूल रूप से नहीं आंका जाना चाहिए।

> "21. .....साक्ष्य का उसकी अंतर्निहित संगतता और कहानी की अंतर्निहित संभाव्यता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। निर्विवाद तथ्यों के साथ साख योग्य संगतता, साक्षी का 'साख' साक्षी पेटी में उनके कार्य निष्पादन, उनकी प्रेक्षण शक्ति आदि को प्रभावित करता है।"

36. सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य में यह न्यायालय ने कहाः (एससीसी पृष्ठ 180, पैरा 13)

> "13. सामान्यतः, चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य केवल संपुष्टि करने वाला होता है। यह साबित करता है कि चोटों को कथित तरीके से किया जा सकता था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बचाव पक्ष चिकित्सा साक्ष्य का जो उपयोग कर सकता है वह यह साबित करने के लिए है कि चोट संभवतः कथित तरीके से नहीं हो सकती थी और इस तरह से प्रत्यक्षदर्शियों को बदनाम करना। हालांकि, जब तक चिकित्सा साक्ष्य अपनी बारी में इस हद तक नहीं जाता है कि वह प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा अभिकथित तरीके से होने वाली चोटों की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को उसके और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कथित असंगति के आधार पर बाहर नहीं फेंका जा सकता है।"

39. इस प्रकार, ऐसे मामलों में कानून की स्थिति जहाँ चिकित्सा साक्ष्य और चश्मदीद साक्ष्य के बीच विरोधाभास है, को इस आशय से स्पष्ट किया जा सकता है कि हालाँकि एक गवाह की आँखों देखी गवाही का चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में अधिक साक्ष्यीय मूल्य है, जब चिकित्सा साक्ष्य आँखों देखी गवाहों को असंभव बना देता है, जो साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक प्रासंगिक कारक बन जाता है। हालाँकि, जहाँ चिकित्सा साक्ष्य इतनी दूर तक जाता है कि यह नेत्र संबंधी साक्ष्य के सत्य होने की सभी संभावनओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, नेत्र संबंधी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सकता है।"

16. विद्वत राज्य के वकील ने उचित रूप से आग्रह किया है कि यदि चिकित्सा और चश्मदीद साक्ष्य विपरीत है तो चश्मदीद साक्ष्य अवश्य अभिभावी होना चाहिए। इस पहलू के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई है और इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में सिद्धांत निर्धारित किया गया है। विद्वत अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा गहन विचार-विमर्श और अभिलेख पर साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के बाद अभिलिखित और दिए गए निष्कर्ष और निर्णय ने अभिनिर्धारित किया कि चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की है कि कठोरता 1 से 3 घंटे के भीतर शुरू होती है और 36 घंटे के बाद समाप्त हो जाती है.चिकित्सा अधिकारी पी डब्लू 8 की 36 घंटे के बाद मृत शरीर से कठोरता के पूरी तरह गायब होने के बारे में कथित राय चिकित्सकीय रूप से सही नहीं है और यह इस विषय पर उसकी जानकारी की कमी हो सकती है और वह बचाव पक्ष के वकील द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए उदार था.इसके अलावा, विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश ने बी. एल. बंसल एडवोकेट द्वारा लिखित मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस डाइजेस्ट (पृष्ठ 422 पर 1996 संस्करण) का सही उल्लेख किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कठोरता 12 से 24 घंटे तक बनी रहती है और फिर समाप्त हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जितनी तेजी से कठोरता दिखाई देती है, यह उतना ही कम समय में बरकरार दिखाई देती है।

इसके अतिरिक्त, विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश ने बूलिन हुल्डर बनाम राज्य 13 में इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामले को संदर्भित किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत के एक ही वातावरण में, कठोरता एक घंटे से दो घंटे में शुरू हो सकती है और 18 से 24 घंटे के भीतर गायब होना शुरू हो सकती है। इसलिए, विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मोटे तौर पर जितना तेजी से कठोर हड्डी दिखाई देती है, उतना ही कम समय लगता है और आगे सही रूप से यह अवलोकन किया है कि कठोर हड्डी मृत शरीर के कुछ हिस्सों में मौजूद होगी। चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू ८ के अनुसार मृतक की मृत्यु के समय का कोई सवाल नहीं है। यह 24 घंटे से पहले होना चाहिए जो रिगर मोर्टिस के गायब होने की अधिकतम सीमा है। चिकित्सा अधिकारी पी डब्लू ८ के कथित दृष्टिकोण में विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दोष पाया गया और अभिनिर्धारित किया कि उसने अपने प्रतिपरीक्षा में सही ढंग से अभिसाक्ष्य नहीं दिया है - किसी मृत व्यक्ति के समय के बीत जाने के बारे में जांच।उन्होंने कठोरता के लिए समय को 30 से 36 घंटे तक बढ़ा दिया है और आगे सही अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सा अधिकारी पी डब्लू 8 ने अपने साक्ष्य में चिकित्सा न्यायशास्त्र के नियम के विपरीत बयान दिया है। इसलिए, विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय में सही अभिनिर्धारित किया है कि यह अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए प्रतिरक्षा का आधार नहीं हो सकता है। अपीलार्थी के इस दावे को कि मृतक 16.07.1996 की सुबह में मारा गया है और इस आरोप को कि अभियुक्त को मामले में झूठा फंसाया गया है, विद्वत अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है और आक्षेपित निर्णय में वैध और ठोस कारण देकर उच्च न्यायालय द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है। उचित रूप से, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत वकील ने इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है कि आरोप लगाने के लिए चिकित्सा और नेत्र साक्ष्य के बीच नेत्र साक्ष्य को वरीयता दी जानी चाहि। यह सही कानूनी स्थिति है जैसा कि पीडब्लू 2, पीडब्लू 3, पीडब्लू 5 और पीडब्लू 7 के साक्ष्य के बयान पर भरोसा करने के बाद दोनों अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है। इसलिए, हमें इस मामले के इस पहलू पर कोई गलत तर्क नहीं मिलता है। ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में मामले के उपरोक्त पहलू पर विद्वान वरिष्ठ वकील की

प्रस्तुतियों में कोई सार नहीं है, जिनके निर्णय मामले की वास्तविक स्थिति पर बिल्कुल लागू नहीं होते हैं।

17. उच्च न्यायालय के साथ-साथ विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा समवर्ती निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और इसमें अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए दोषसिद्धि और दंडादेश का आदेश रिकॉर्ड पर कानूनी साक्ष्य के आधार पर और उसी के उचित मूल्यांकन पर है। इसलिए, यह कानून में गलत नहीं है क्योंकि निष्कर्ष वैध और तर्कसंगत कारणों से समर्थित है। पूर्वगामी कारणों से, आक्षेपित निर्णयों एवं आदेश मैं इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।इसलिए, अपील योग्यता से रहित है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

[चंद्रमौली कृष्ण प्रसाद, न्यायमूर्ति]

[वी० गोपाल गौड़ा, न्यायमूर्ति]

नयी दिल्ली

22 मार्च, 2013

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।